एस तिवाना, एसीजे और जवाहर लाल गुप्ता के समक्ष

ईश्वर सिंह शर्मा और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, -प्रतिवादी

1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 16470

18 सितंबर 1991.

भारत का संविधान, 1950-कला. 226-तदर्थ राहत-अनुदान--कर्मचारियों को किया गया अतिरिक्त भुगतान-अतिरिक्त महंगाई भत्ते के विरुद्ध समायोजन-अतिरिक्त भुगतान का विवरण और समायोजन की विधि निर्धारित-उसके बाद वेतनमान का आवधिक संशोधन-1974 संकेत के अनुसार तदर्थ राहत की राशि निर्दिष्ट करने वाले आदेश समायोजित किया जाए-याचिकाकर्ता ए.डी.ए. का भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। समायोजन खंड के अनुसार - राज्य तदर्थ राहत को समायोजित करने का हकदार है - ऐसा समायोजन किसी भी नियम या कानून का उल्लंघन नहीं करता है और न तो अनुचित है और न ही मनमाना है - याचिकाकर्ता लंबे विलंब के बाद न्यायालय का रुख कर रहे हैं - याचिकाएं कमियों के आधार पर खारिज की जा सकती हैं।

माना गया कि वर्ष 1972 में सरकार द्वारा दी गई 'तदर्थ' छूट वास्तव में 'तदर्थ' थी। बाद की कार्रवाइयों और घटनाओं से स्पष्ट रूप से पता चला है कि तदर्थ राहत प्रदान करते समय कोई निश्चित फॉर्मूला या मानदंड निर्धारित या पालन नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में, हम अतिरिक्त महंगाई भत्ते की भविष्य की किस्तों के लिए कर्मचारियों द्वारा पहले से ही ली जा रही अतिरिक्त राशि को समायोजित करने के निर्णय में सरकार की कार्रवाई में कुछ भी गलत नहीं पाते हैं। इसने किसी भी नियम या कानून का उल्लंघन नहीं किया. इसने अनुचित कार्य नहीं किया। इसने पहले से भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को वापस भी नहीं लिया या वसूल नहीं किया। इसने तदर्थ राहत का भुगतान भी नहीं रोका। इसमें केवल यह निर्देश दिया गया कि अतिरिक्त भत्ता अतिरिक्त राशि को समायोजित करने के बाद दिया जाएगा। तदर्थ राहत पहले ही दी जा चुकी है। हमें कुछ भी मनमाना नहीं लगता। हमें आदेश में कोई अवैधता नहीं मिली.

माना गया कि राज्य द्वारा स्वीकृत तदर्थ राहत और अतिरिक्त महंगाई भत्ते के माध्यम से भुगतान केवल कल्याणकारी उपायों की प्रकृति में है। इनका वास्तव में उपलब्ध संसाधनों से संबंध होना चाहिए। समान रूप से सिविल सेवक को दूसरों की कीमत पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

माना गया कि 1974 के आदेशों को वर्ष 1990 में चुनौती दी गई है। मामले पर विचार करने पर, हम आपत्ति में योग्यता पाते हैं। इन सभी वर्षों के दौरान याचिकाकर्ताओं ने मार्च, 1974 के आदेश के खिलाफ एक फुसफुसाहट भी नहीं उठाई। वास्तव में, उन्होंने उस आदेश के तहत सभी लाभ प्राप्त किए जिसे अब विवादित करने की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं वेतनमान को वर्ष 1979 और 1986 में संशोधित

किया गया है, लेकिन अन्यथा भी, हमें याचिकाकर्ताओं की ओर से लंबी चुप्पी का कोई औचित्य नहीं मिला है। देरी के आधार पर ही याचिकाएं खारिज किये जाने योग्य हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क है कि यह कार्रवाई का एक आवर्ती कारण है। हम इस तर्क को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 20 मार्च 1974 के पत्र और उसके अनुलग्नकों के अनुसार तय किया गया था। यहां तक कि एक मुकदमा भी पूरी तरह से सीमा से वर्जित होगा। ऐसी स्थिति में, हम याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए इस विलंबित दावे पर विचार करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के इच्छुक नहीं हैं। (पैरा 11)

नित्या नंद डी. हरियाणा राज्य (सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 5563-ए 1989 का निर्णय 23 अप्रैल 1990 को)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका

प्रार्थना है कि याचिकाकर्ताओं को निम्नलिखित राहत दी जाए:-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ताओं को निम्नलिखित राहत दी जाए:-

(i) सर्टिओरी प्रकृति की एक रिट जारी की जाएगी जिसमें आदेश परिशिष्ट पी-3 से संबंधित उत्तरदाताओं संख्या 1 से 2 के रिकॉर्ड मंगाए जाएंगे और उसके अवलोकन के बाद आदेश परिशिष्ट पी के पैराग्राफ संख्या 3 और 4 की मांग की जाएगी। -3 को रद्द किया जाए।

उत्तरदाताओं को 31 मार्च 1979 तक की गई कटौती को वापस करने और 1 अप्रैल 1979 से सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधित वेतनमान में याचिकाकर्ताओं के वेतन के पुनर्निर्धारण के बाद याचिकाकर्ताओं को बकाया राशि की अनुमति देने का भी निर्देश दिया जाए। और 1 जनवरी, 1986.

(ii) याचिकाकर्ताओं को हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 1980 और अन्य में निहित मौजूदा परिलब्धियों की परिभाषा के आपत्तिजनक हिस्से को हटाकर, यदि आवश्यकता हो तो विकल्प की तारीख में बदलाव सहित परिणामी राहत भी दी जानी चाहिए। याचिका के साथ संलग्न अनुबंध पी-3 के अनुसार, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को देय कुल परिलब्धियों में से कोई भी कटौती करने से रोकने का निर्देश दिया जाए।

(iii) याचिकाकर्ताओं के लाभ के लिए कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसे माननीय उच्च न्यायालय इस मामले की विशेष परिस्थितियों में उचित समझे,

(iv) इस याचिका की लागत के बारे में उन्हें अवगत कराया जाए।

याचिकाकर्ताओं के लिए जे.एस. यादव, अधिवक्ता, आर.एस. मित्तल, और एच.एस.हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता, जी.के. चतरथ, अधिवक्ता, के साथ।

एच. एल. सिब्बल, महाधिवक्ता, हरियाणा के साथ जे. के. सिब्बल, अधिवक्ता और सुश्री केरन रंधावा और संजीव शर्मा, अधिवक्ता उत्तरदाताओं.

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता जे

(1) 17 साल से भी पहले 20 मार्च 1974 को हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया था. इसी आदेश के द्वारा, इसने 'तदर्थ' राहत की अतिरिक्त राशि के समायोजन का भी आदेश दिया था जो वर्ष 1972 में दी गई थी। इस समायोजन ने इन 268 याचिकाओं के लिए 'कार्रवाई का कारण' प्रदान किया है। सिविल रिट याचिका संख्या, 8995, 10075, 10235, 11905, 12037, 12386, से 12390, 12908, 13627, 13875, 14418, 14473, 14955, 14653, 14643, 14936, 1 5094, 16641, 16793, 16825, 14725, 14935, 14937.. 14911, 15012, 15058, 15521, 15323, 15324, 15330, 15703, 16566, 15354, 15355, 15256, 15445, 15557, 15569 से 15572, 1 5626, 15676, 15704, 15733.1 15875, 16434, 15877, 15993, 15551, 16015, 16186, 16315, 16379, 16380, 16415, 16432, 16433, 16435, 16436, 16437, 16453, 16469, 16490, 15992. 16788, 16 503, 16555, 16726, 16811, 16826, 1990 का, 2310 1991 का , 16907, 16908, 12798, 1990 का 16837, 81, 86, 87, 92, 102, 161, 194, 307, 196, 232 से 235, 366, 389, 407, 418, 423, 460, 461, 469, 484 , 523, 535, 567, 642, 658, 659, 660, 663, 670, 705, 708, 729, 774. 796, 797, 798, 799, 801, 825, 879, 949, 950, 975, 981। 1003 , 1059. 1060, 1063, 1079, 1344, 1397, 1398, 1402, 1405, 1415, 1419, 1428, 1429, 1430 से 1434. 1440, 1442 से 1444, 1446, 1453, 1458, 1463, 1967, 1970, 1465 , 1466, 1467, 1469, 1472, 1468, 1470, 1471, 1473, 1504, 1505, 1508, 1507, 1516, 1517, 1519, 1531, 1540, 1542 से 1546, 1592, 1619, 1667, 1681, 1715, 1688 , 1691, 1716. 1754, 1773, 1808, 1816, 1824, 1991 का 1889. 1990 का 15630, 1890. 1907, 1913, 1931, 1948, 1965 से 1967, 1969, 1970 , 2087, 2311. 2411, 2827, 2956 , 3032, 360, 3014. 3157, 3154, 3363, 3714, 3778. 3838, 3887, 3967. 4023, 4051, 4052,

4054, 4082, 4230, 4296, 4340, 4465, 4477, 4478, 3837, 3868. 4501 , 4682, 4767, 4768 से 4771, 4868. 4966, 5555, 5589, 5759, 6161, 6176, 6177, 6305, 6640.1 6742, 6743, 6906. 7166. 7167, 7445 , 7968, 7971, 1991 का 8623, 6596, 5320, 1991 का 9705। हरियाणा राज्य के बड़ी संख्या में कर्मचारी हमारे सामने हैं और उनका दावा है कि यह कार्रवाई बिल्कुल मनमानी और अनुचित है। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का तर्क है कि याचिकाकर्ता पुराना दावा करते हैं और इसमें बहुत देरी होती है। गुण-दोष के आधार पर, उनकी ओर से यह कहा गया है कि कार्रवाई बिल्कुल न्यायसंगत और निष्पक्ष है।

(2) संबंधित तर्कों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, सी.डब्ल्यू.पी. में बताए गए कुछ तथ्य। 1990 का नंबर 16470 (ईश्वर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) पर ध्यान दिया जा सकता है।

(3) विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। सरकार ने 27/29 जून, 1972 और 19 दिसंबर, 1972 के अपने आदेशों के जरिए अपने कर्मचारियों को तदर्थ राहत दी थी। सरकार ने, 20 मार्च, 1974 के आदेश के जरिए आगे राहत देने का फैसला किया। 1 मई, 1973, 1 सितंबर, 1973, 1 अक्टूबर, 1973 और 1 जनवरी, 1974 से अतिरिक्त महंगाई भत्ता। दरें और गणना की विधि निर्दिष्ट की गई थी। यह भी आदेश दिया गया था कि "अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान करते समय इस पत्र के अनुबंध I के कॉलम 5 और 7 में दर्शाए अनुसार तदर्थ राहत की राशि का एक हिस्सा समायोजित किया जाएगा" (जोर दिया गया)। अतिरिक्त भुगतान का विवरण और समायोजन की विधि स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई थी। इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ताओं ने इस पत्र के अनुसार अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान स्वीकार कर लिया है और इस तथ्य के बावजूद कि उसके बाद वेतनमान में समय-समय पर संशोधन होते

रहे हैं, तदर्थ राहत के एक हिस्से के समायोजन से याचिकाओं का यह समूह सामने आया है। हमारे सामने।

(4) जब यह मामला प्रस्ताव से पहले सुनवाई के लिए आया पीठ ने याचिकाकर्ताओं को एक व्यापक पुन: निर्माण करने का निर्देश दिया। प्रस्तुति और उत्तरदाताओं को प्रतिनिधित्व तय करने के लिए निर्देशित किया गया था-

'बोलने का आदेश' पारित करके भेजा जाना। यह किया जा चुका है। याचिकाकर्ताओं द्वारा 'स्पीकिंग ऑर्डर' को उनकी प्रतिकृति के साथ अनुलग्नक पी-7 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के कारणों को संक्षेप में बताया जा सकता है। मोटे तौर पर ये हैं:-

(1) महंगाई भत्ते की एक विशेष मात्रा प्राप्त करने का कोई कानूनी या निहित अधिकार नहीं है।

(2) वर्ष 1972 में 'जीवनयापन की लागत के संदर्भ में' कोई फार्मूला अपनाए बिना तदर्थ राहतें प्रदान की गईं।

(3) 20 मार्च 1974 के पत्र द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रत्येक 8 अंक की वृद्धि पर अतिरिक्त महंगाई भत्ता प्रदान किया गया। किसी भी फॉर्मूले के संदर्भ के बिना स्लैब प्रणाली पर पहले दी गई तदर्थ राहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक फॉर्मूला के आधार पर अनुमेय से अधिक पाई गई थी।

(4) गणना के आधार पर यह पाया गया कि तदर्थ राहत के माध्यम से दिया गया महंगाई भत्ता स्वीकार्य की तुलना में वेतन स्लैब की विभिन्न श्रेणियों में 9.40 रुपये से 45.00 रुपये तक अधिक था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ता।"

(5) एक सिद्धांत के रूप में, परिलब्धियों को कम करना या निकाली गई अतिरिक्त राशि की वसूली करना वांछनीय नहीं माना गया। कर्मचारियों द्वारा. यह निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त महंगाई भत्ता पहले से दी गई अतिरिक्त तदर्थ राहत के समायोजन के बाद ही मिलेगा। किसी कानून के तहत महंगाई भत्ता देने की गारंटी नहीं है।लेकिन यह एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से दी गई रियायत है। देय राशि से अधिक दी गई तदर्थ राहत को समायोजित किया जा सकता है।

वेतनमान को 1 अप्रैल, 1979 और 1 जनवरी, 1986 से संशोधित किया गया था जब परिलब्धियों में पर्याप्त वृद्धि की गई थी।

(5) भले ही एक विस्तृत प्रतिकृति दायर की गई हो और अभ्यावेदन को खारिज करने का आदेश अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत किया गया हो, तथ्यात्मक आधारों पर हमला नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने केवल 20 मार्च 1974 के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह मनमाना है। यह भी तर्क दिया गया है कि बड़ी संख्या में इसी तरह की याचिकाओं को पहले ही अनुमति दी जा चुकी है, हम वर्तमान याचिकाओं को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। दूसरी ओर, विद्वान महाधिवक्ता श्री एच.एल. सिब्बल ने देरी की आपत्ति उठाने के अलावा तर्क दिया कि कार्रवाई बिल्कुल न्यायसंगत और निष्पक्ष थी।

(6) पक्षों के वकील को सुनने और दलीलों पर गौर करने के बाद हमने पाया कि वर्ष 1972 में सरकार द्वारा दी गई 'तदर्थ' राहत वास्तव में 'तदर्थ' थी। बाद की कार्रवाइयों और घटनाओं से स्पष्ट रूप से पता चला है कि तदर्थ राहत प्रदान करते समय कोई निश्चित फॉर्मूला या मानदंड निर्धारित या पालन नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में, हम अतिरिक्त महंगाई भत्ते की भविष्य की किस्तों के लिए कर्मचारियों द्वारा पहले से ही ली जा रही अतिरिक्त राशि को समायोजित करने के निर्णय में सरकार की कार्रवाई में कुछ भी गलत नहीं पाते हैं। इसने किसी भी नियम

या कानून का उल्लंघन नहीं किया. इसने अनुचित कार्य नहीं किया। इसने पहले से भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को वापस भी नहीं लिया या वसूल नहीं किया। इसने 'तदर्थ राहत' का भुगतान भी नहीं रोका। इसने केवल यह निर्देश दिया कि पहले से दी गई तदर्थ राहत की अतिरिक्त राशि को समायोजित करने के बाद अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। हमें कुछ भी मनमाना नहीं लगता। हमें आदेश में कोई अवैधता नहीं मिली.

(7) यह याद रखना भी उचित है कि देश - करदाता - सिविल सेवकों के वेतन और भत्ते का बोझ वहन करता है। राज्य के सामने आने वाली वित्तीय बाधाओं को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राज्य द्वारा स्वीकृत तदर्थ राहत और अतिरिक्त महंगाई भत्ते के माध्यम से भुगतान केवल कल्याणकारी उपायों की प्रकृति में हैं। इनका वास्तव में उपलब्ध संसाधनों से संबंध होना चाहिए। समान रूप से सिविल सेवकों को दूसरों की कीमत पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

(8)मामले पर विचार करने पर हम संतुष्ट हैं कि जिस परिसर पर सरकार ने विवादित आदेश पारित किए हैं वह वैध है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में सरकार द्वारा किए गए परिणामी समायोजन को हमारे द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है।

(9) **नित्या नंद बनाम हरियाणा राज्य** [1](1) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि रिट याचिका अनुमति देने योग्य है। हम इस फैसले से गुजर चुके हैं. हमें यह भी सूचित किया गया है कि नित्या नंद के मामले (सुप्रा) में निर्णय के आधार पर, कई अन्य याचिकाओं पर भी निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित श्री सिब्बल ने बताया कि राज्य सरकार ने नित्या नंद के मामले में विशेष अनुमति के लिए याचिका दायर की है और अन्य मामलों में भी अपील, याचिका दायर कर रही है। ऐसे में हमने इस मामले को बड़ी बेंच के पास नहीं भेजने का फैसला

[1] CWP No. 5563-A of 1989 decided on April 23, 1990.

किया है।' अन्यथा भी, हम पाते हैं कि नित्या नंद के मामले में निर्णय (**हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज लेक्चरर्स एसोसिएशन बनाम हरियाणा राज्य** [2](2) के फैसले पर आधारित है। यह निर्णय उन कॉलेज शिक्षकों के मामले में था जिन्हें कोई अनुमति नहीं दी गई थी। वर्ष 1972 में राज्य सरकार के आदेश के तहत तदर्थ राहत। नतीजतन, उनके मामले में, अतिरिक्त भुगतान के किसी भी समायोजन का सवाल ही नहीं उठता। यह निर्णय अन्य सरकारी कर्मचारियों के मामलों में लागू नहीं था। वेतनमान कॉलेज व्याख्याताओं की संख्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर निर्धारित की गई थी, जबकि सरकार के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों को समय-समय पर अतिरिक्त महंगाई भत्ते की प्रकृति में राहत दी गई थी। इसलिए, कॉलेज व्याख्याता उन लोगों से पूरी तरह से अलग हैं। वहां सिविल सेवक थे और वहां कोई उपमा नहीं दी जा सकती थी-मैं नित्या नंद के मामले में वैसा ही हूं। इसके अलावा, क्योंकि मामला वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित बताया गया है, मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

(10) यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि कॉलेज लेक्चरर्स एसोसिएशन के मामले का निर्णय जी. सी. मित्तल, जे. (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) द्वारा किया गया था। उस निर्णय के बावजूद और नित्या नंद के मामले में निर्णय उनके लॉर्ड-शिप के समक्ष रखे जाने के बावजूद, जी.सी.मित्तल, जे. और एस.एस. ग्रेवाल, जे. की मोशन बेंच ने 5 फरवरी, 1991 को इसे उचित माना था। याचिकाकर्ताओं को अभ्यावेदन देने और उत्तरदाताओं को स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश दें। इसके बाद, एक विस्तृत आदेश रिकॉर्ड पर आ गया है जो नित्या नंद के मामले में बेंच को उपलब्ध नहीं था। इस आदेश में बताई गई विस्तृत स्थिति को देखते हुए, मामले को बड़ी बेंच को भेजने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

[2] CWP No. 966 of 1986 decided on July 18, 1988

(11) गौरतलब है कि नित्या नंद के मामले में देरी को लेकर आपत्ति भी नहीं उठाई गई थी. वर्तमान मामले में, विद्वान महाधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया दावा बिल्कुल पुराना है। 1974 के आदेशों को वर्ष 1990 में चुनौती दी गई है। मामले पर विचार करने पर हमें आपत्ति में दम नजर आता है। इन सभी वर्षों के दौरान याचिकाकर्ताओं ने मार्च, 1974 के आदेश के खिलाफ एक फुसफुसाहट भी नहीं उठाई। वास्तव में, उन्होंने उस आदेश के तहत सभी लाभ प्राप्त किए जिसे अब विवादित करने की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं वेतनमान भी दिया गया है। वर्ष 1979 और 1986 में संशोधित किया गया, लेकिन अन्यथा भी, हमें याचिकाकर्ताओं की ओर से लंबी चुप्पी का कोई औचित्य नहीं मिला। देरी के आधार पर ही याचिकाएं खारिज किये जाने योग्य हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क है कि यह कार्रवाई का एक आवर्ती कारण है। हम इस तर्क को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 20 मार्च 1974 के पत्र और उसके अनुलग्नकों के अनुसार तय किया गया था। यहां तक की। एक मुकदमा पूरी तरह से सीमा से वर्जित होगा। ऐसी स्थिति में, हम याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए इस विलंबित दावे पर विचार करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के इच्छुक नहीं हैं।

(12) तदनुसार, हमें इन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिली, जिन्हें एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। मामले की परिस्थितियों में, हम पार्टियों को उनकी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा